>

Title: Regarding Welfare measures for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers.

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): महोदय, देश में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजनाएं हैं, जो सरकार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर चलाई जा रही हैं, उसमें आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्व में जिस तरह से आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे थे, उससे जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे, जो लाभ आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा था।

20.12 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

महोदय, इसमें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी की जो हमारे बहनें होती हैं, उनसे अवैतनिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही आंगनवाड़ी की जो सहायिका और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता होती हैं, उनकी नियुक्ति, भर्ती सहित स्कीम के कार्यान्वयन संबंधी सभी मसले राज्य की सरकारों के द्वारा तय किए जाते हैं, जो जिला स्तर और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर उनकी समीक्षा के साथ वे काम पूरे किए जाते हैं। निश्चित रूप से आंगनवाड़ी की जो हमारी सहायिका हैं, वे बहुत मेहनत कर रही हैं और उसके कारण उनको जो मानदेय देने की बात थी, उसमें भी अभी हमारी सरकार ने काफी बदलाव किया है। अगर हम उनके काम के विषय में देखें तो आंगनवाड़ी स्कीम का लक्ष्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का समग्र विकास करना है। इसमें पूरक पोषण, सकल, स्कूल के पूर्व की जो अनौपचारिक शिक्षा है, उसके साथ-साथ पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाओं के जो पैकेज प्रदेश सरकार और केन्द्र

सरकारों के द्वारा लोगों की जरूरत के लिए बनाए जाते हैं, उसमें उन आंगनवाड़ी की बहनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वास्तव में पूरी दुनिया में वर्ष 2030 तक सस्टेनेबल गोल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा देश गाँवों का देश है। गाँव-गाँव तक शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और पोषण के प्रति लोग जागरूक हों, संवेदनशील हों और समय पर पोषण के कार्यक्रमों को चलायें और उनका लाभ भी लें। उन्हें किस तरह से बच्चों का पालन-पोषण करना है, इसके साथ-साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, ज्यादातर महिलाएं एनीमिक होती हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, जो छोटे बच्चे हैं, उनके जो टीकाकरण के कार्यक्रम होते हैं, जो सात ऐसी गंभीर बीमारियाँ हैं, टीकाकरण के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ रखने की एक हमारे देश में थी।

हमारी जो आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिकाएं और कार्यकर्ता हैं, उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वह निश्चित रूप से ये छ: काम कर रही हैं। हमारी जो पहले की सरकारें थीं, उस समय बहुत विशेष ध्यान इस पर नहीं जा पाया, चूंकि उस समय ऐसी बात भी नहीं थी। वर्ष 2018 में आंगनवाड़ी केन्द्रों की जो कार्यकर्ता थीं, उनका मानदेय प्रतिमाह 3000 रुपये से बढ़ा कर 4500 रुपये किया गया है। उसके साथ ही साथ हमारी जो सहायिकाएँ होती हैं, उनको 2250 रुपये मिलता था, उसको 3500 रुपये किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने अन्य अनेक तरह के मानदेय भी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को देने का काम किया है और उन योजनाओं को स्वीकार किया है। वास्तव में आज कल के युग में 4500 रुपये में जिस तरह की वह सेवा कर रही हैं और जिस तरह से वह गाँवों में जाकर कामकाज कर रही है, इसके लिए उनको अधिक मानदेय मिलना चाहिए। अभी मैं इस पर भी बात करूँगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारे देश में लगभग 14 लाख ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता काम कर रही हैं। उन्होंने गाँवों में निरंतर ऐसे प्रयास करके अपनी उत्तम सेवाएँ भी दी हैं। हालांकि यह भी तय है कि हमारी जो योजनाएँ हैं, ये इस तरह की योजनाएँ हैं, जिनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा

भी है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक हजार दिन का पोषण कार्यक्रम अपने देश के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए चलाया है। गर्भावस्था का जो समय होता है, उन्होंने उसके लिए दो साल जोड़ें। उन्होंने 730 दिन और 270 दिन जोड़ कर एक हजार दिन की स्कीम बनाई है। उसके पीछे यह उद्देश्य था और वैज्ञानिक तथ्य भी है कि गर्भावस्था से लेकर दो वर्ष तक अगर शिशु का ठीक ढंग से पालन पोषण होता है, उसकी देख-भाल ठीक तरीके से होती है, तो निश्चित रूप से वह बालक कुपोषित नहीं होता है। आयु के हिसाब से उसका भार और लम्बाई इस तरह से बढ़ती है तो जो पोषित बच्चा होता है, वह देश के लिए एक स्वस्थ नागरिक के रूप में अपनी सेवाएँ देता ही है, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। हमारी आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं, इनकी भूमिका को हम अपने देश के लिए समझ सकते हैं। उसी क्रम में सरकार द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर उनके प्रशिक्षण के लिए चलाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों की जो बहनें हैं, उनके लिए कई ऐसे मॉड्यूल्स हैं, जिससे उनकी क्षमता में किस तरह से वृद्धि हो, उनको प्रशिक्षण भी देने का कार्यक्रम किया है। उसमें लगभग 9 लाख के करीब ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। उसमें से लगभग 3 लाख के करीब इस तरह की कार्यकर्ताएँ हैं, जिनको डिजिटल प्रशिक्षण भी दिया गया है। आज कल जिस तरह से एक-एक कार्यक्रम की जानकारी और सूचनाएँ सरकार के द्वारा एकत्रित की जा रही हैं, निश्चित रूप से सरकार प्रशंसा की पात्र है। प्रत्येक योजना की सारी सूचनाएँ डेटावाइज हमारी सरकार के पास उपलब्ध रहे, जिससे आगे उनको योजना बनाने में सफलता मिले। अगर उसके अनुरूप योजनाएँ बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके व्यापक परिणाम हमको प्राप्त होंगे। हमारे सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा।

इसी क्रम में हमारी सरकार ने जो डिजिटल प्लेटफार्म है, उसको तैयार किया है। आंगनवाड़ी केन्द्रों की ऐसी कार्यकर्ताओं को डिजिटल फोन, स्मार्ट फोन भी दिए गए हैं। उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वह गाँवों में जहाँ-जहाँ पर

जाएंगी, वहां पर वह डेटा एकत्रित करेंगी। बच्चों की आयु के अनुसार उसका भार, उसकी लम्बाई, महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में, टीकाकरण के विषय में लोगों को जागरूक करेंगी। उन सारी योजनाओं के बारे में भारत सरकार का जो ऐप है, उस पर फीड करेंगी, जिससे यहां पर सारी सूचनाएँ एकत्रित होंगी।

निश्चित रूप से अगर आप देखें तो गांवों में आंगनवाड़ी की बहनें कर रही हैं, वह निश्चित रूप से ऐसा काम है, जिसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और उसके अनुरूप उनको सुविधाएं भी देने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए, क्योंकि यह भी जरूरी है। अभी कई ऐसी जानकारियां आयी थीं कि कई ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो किराये के मकानों में चल रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन बनाएंगे। काफी भवन बन चुके हैं। लगभग 4 लाख आंगनवाड़ी के ऐसे केंद्र हैं, जिनके भवनों का निर्माण होना है। सरकार ने उसको भी मनरेगा से जोड़ दिया है और पांच लाख रुपये तक मनरेगा के धन का उपयोग भवन के निर्माण में किया जाता है और उसमें अलग से स्वच्छता कार्य योजना के लिए पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए दस हजार रुपये और 12 हजार रुपये प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय के लिए भी दिया है। यह निश्चित रूप से सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि आंगनवाड़ी के लिए ठीक-ठाक और अच्छे भवन उपलब्ध हो जाएं। इसके लिए उन्होंने यह भी कहा है कि जहां कहीं भी जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वहां 600 वर्ग फीट के मकानों को किराये पर लेकर, जहां पेयजल इत्यादि की व्यवस्थाएं हों, उसमें चलाने की सुविधा भी सरकार ने दी है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे केंद्र हैं, जहां शौचालय और पेयजल की सुविधाएं नहीं हैं। उसमें 4 लाख के आस-पास ऐसे आंगनवाड़ी के केन्द्र हैं, जहां अभी ठीक ढंग से टॉयलेट्स उपलब्ध नहीं हैं और दो लाख के करीब ऐसे हैं, जहां पेयजल की व्यवस्था भी हमारी सरकार को करनी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि यह आवश्यक है, क्योंकि कोविड की वजह से आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहे हैं। नवंबर, 2020 से कुछ आंगनवाड़ी केंद्र, जो कंटैनमेंट जोन में आते हैं, उनको छोड़कर धीरे-धीरे आंगनवाड़ी के केन्द्रों को खोलने का काम प्रारम्भ कर

दिया गया है। इसलिए वहां सुसज्जित भवन बने। कोविड के बाद जो मानदंड तय किए गए हैं, उसके अनुरूप फिर से हमारे कार्यक्रम प्रारम्भ हो रहे हैं। जो पहले से स्कूल से पूर्व की शिक्षा है, उसके लिए अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन उनको भी निर्देशों के अनुसार प्रारम्भ कर दिया जाएगा। लेकिन कुपोषित बच्चों, अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताओं की गहन निगरानी का काम भी हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता कर रही हैं और उसके अनुरूप जो आवश्यकता होती है, जैसी हमारी सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं या ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन सब में भी वे अपनी तरफ से योगदान देकर ऐसी खाद्य सामग्री जिसमें कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा इस तरह की हो जो कुपोषण से बच्चों को मुक्त कर सकें, ऐसी सारी व्यवस्थाएं और आहार उपलब्ध कराने का काम उन्होंने किया है और कोविड के दौरान भी किया है। कोविड में आंगनवाड़ी के केन्द्र भले ही बंद रहे हैं, लेकिन जो सरकार की योजनाएं आयीं, कोविड के लिए जागरुक करना हमारे लिए चुनौती थी। हमारा देश 130 करोड़ की आबादी वाला देश है और उस देश में जहां आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है, वहां संक्रमण फैलने की संभावना बहुत ज्यादा थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश को जागरुक किया। अलग-अलग समय पर ऐसे निर्णय लिए और उन निर्णयों के अनुरूप देश में व्यवस्थाएं कीं, जिसके कारण कोविड 19 के संक्रमण के दौरान भी हमारे देश में कोई इस तरह की स्थिति नहीं आयी है, जिसमें हमें यह लगे कि हम स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं या स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। स्थिति नियंत्रण में रही है और कोविड के दौरान भी जो ऐसे जरूरी काम थे, कुपोषण को दूर करने के काम हों, महिलाओं के स्वास्थ्य के काम हों, बच्चों की मृत्यु दर को कम करने की बात हो, महिलाओं की मृत्यु दर पर भी काम हुआ और उसके साथ-साथ संस्थागत प्रसव इत्यादि योजनाओं से संबंधित जानकारियों और वस्तुओं, दवाओं को पहुंचाने का काम और उसके साथ-साथ टीकाकरण के प्रति भी लोगों को जागरुक करने का काम आंगनवाड़ी की हमारी स्वास्थ्यकर्मियों ने किया है। एक तरह से आप देखें तो पहले लोग आंगनवाड़ी के विषय में जानकारी

ही नहीं रखते थे, अब तो दो-दो मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से चल रही हैं। उसके कारण गांवों में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गयी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि उनकी सेवाओं को देखते हुए, जो 4500 रुपये हमारी मुख्य कार्यकर्ता को मिल रहं हैं, मैं समझता हूं कि उसमें राज्य सरकार का भी योगदान होता है, लेकिन अपनी तरफ से आप अगर इसमें कोई प्रावधान करें, जिससे उनको कम से कम दस हजार रुपये का मानदेय मिल सके तो यह एक बहुत अच्छा मानदेय होगा।

जैसी उनकी सेवाएं हैं, उन सेवाओं के अनुरूप, एक तरह से उनका जो सम्मान है, वह सम्मान करने का काम हम करेंगे।

सभापति जी, इसके अलावा, जो मैंने शुरू में कहा कि ऐसे चार लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं, जहां शौचालय नहीं हैं, दो लाख से अधिक केंद्र ऐसे हैं, जहां पीने का पानी नहीं है, उनको भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करे। मैं चाहता हूँ कि हमारा यह जो रेजोल्युशन है, इसमें संशोधन किए जाएं ताकि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। आंगनवाड़ी के समस्त केंद्रों के अपने अपने भवन हों। भवनों में शौचालय और पेयजल की उत्तम व्यवस्था की जाए। वे जो काम करती हैं, वह गांव-गांव में जाने का काम है, अगर उनको अपने भवन के साथ-साथ कुछ इस तरह की सुविधाएं मिल सकें, जिससे उनका आना-जाना सरल हो सके। भवन में फर्नीचर तथा लाइट आदि अन्य इस तरह की सुविधाएं उनको मिल जाएं। हमें इन सारे कामों को करना चाहिए।

साथ ही साथ हमारे एक साथी ने मुझे यह पत्र दिया है। हालांकि यह राज्य सरकार का विषय है। लेकिन यहां पर माननीय मंत्री जी हैं, तो उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो सीडीपीओ ब्लॉक स्तर पर होती हैं, हमारे साथी ने बताया है कि वे कुछ जगहों पर घूस लेने का काम भी करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि दो हजार रुपये उनके मानदेय से ले लेती हैं। तो भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगे और निश्चित रूप से जैसा उनका काम है और जहां से वे

निकल कर आती हैं, जिस तरह के कामों को वे करती हैं, तो इसकी संभावनाएं तो हैं और इन संभावनाओं को देखते हुए भ्रष्टाचार खत्म हो और आंगनवाड़ी केंद्रों की जो सेवाएं हैं, जिस तरह का उनका काम है, उनको भ्रष्टाचार से मुक्त करने का भी काम करना चाहिए। वैसे मैंने मानदेय बढ़ाने की बात कही है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि हमने जैसे यह कहा है कि कई बार पहले शिकायतें आई हैं, इधर कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं, उनके शोषण की भी बहुत सारी शिकायतें प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुई हैं और उनके लिए एक इस तरह की विधि संचालित है, जो प्रदेश में इस तरह घटनाक्रम होते हैं, उसमें वे काम करती है। ...(व्यवधान) लेकिन जो हमारी केंद्र की सरकार है, उसमें भी माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही थी कि प्रदेश स्तर से तो उन सारे मसलों को देखा जाता है और जो आवश्यक कानूनी कार्यवाही होती है, उसको किया भी जाता है। लेकिन अगर केंद्र स्तर पर भी ऐसी कोई शिकायत आती है, तो माननीय मंत्री जी और सरकार उसका संज्ञान लेती है और संबंधित अधिकारी को उसके लिए कहती है। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि इतना ही यह पर्याप्त नहीं है। यह किया जाता है, लेकिन जिस तरह का एक लंबा स्ट्रक्चर है, एक बड़ा नेटवर्क आंगनवाड़ी का है, तो इसमें कुछ इस तरह की बात जरूर शामिल करनी चाहिए, जिससे आंगनवाड़ी की जो हमारी सहायिकाएं हैं या कार्यकर्ताएं हैं, उनको पूरी तरह से शोषण और भ्रष्टचार से मुक्त करने के लिए कुछ इस तरह से कानून में बदलाव करने चाहिए ताकि जो इस तरह की सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं, उनको हम एक अतिरिक्त आवरण और कवच उपलब्ध करा सकें, जिससे वे शोषण से मुक्त हो सकें।

एक अंतिम बात मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से और कहना चाहूंगा और इस रेजोल्युशन में शामिल करने की प्रार्थना करूंगा कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, वे काम तो कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे परिणाम भी आए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधान मंत्री जी ने और आपने यह अपेक्षा की थी कि हमारे देश में एक बदलाव आए तो वास्तव में कुपोषण को दूर करने में, मुक्त तो

नहीं हुए, लेकिन कुपोषण को दूर करने में भी हमको सफलता मिली है। शिशु मृत्यु दर को भी कम करने में हमें सफलता मिली है। उसके साथ-साथ जो गर्भवती महिलाएं थी या गर्भ के दौरान जो मृत्यु हो जाती थीं, उसमें भी हमको सफलता मिली है। संस्थागत प्रसव भी बढ़ा है और स्तनपान के बारे में भी लोगों की जागरूकता बढ़ी है।

उसके साथ ही साथ, बच्चों का जो दो वर्ष तक का समय होता है, जिसमें उनका मस्तिष्क विकसित होता है, यह वैज्ञानिक तथ्य है और लोग मानते हैं कि दो वर्ष में एक व्यक्ति के दिमाग का विकास हो जाता है, वह फिर पूरे समय में उतना नहीं हो पाता है इसलिए उस महत्वपूर्ण समय के लिए जो योजना बनाई है, उसके लिए भी ये कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनका नियमित रूप से ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रशिक्षण होता है। वहां से उनकी देखभाल की जाती है। आपने स्मार्ट फोन का एप बनाया है, उसके माध्यम से आपको वे सूचनाएं देती हैं। उसकी भी आप जांच और सर्वे करती हैं। एक तरह से यह पूरी इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन गया है कि इसमें हम यह कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी हमारे लिए एक ऐसा नेटवर्क हो गया है, जिसके माध्यम से हम देश की एक बहुत बड़ी समस्या से निजात पाने की स्थिति में आ गए हैं।

मैं अंतिम बात आपसे यही कहूंगा कि इनका मानदेय बढ़ने के अलावा जो आंगनवाड़ी के केंद्रों में सुविधाएं हैं, शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अलावा मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रधान मंत्री जी, आपने और हमारी सरकार ने लोगों के विषय में गरीब और कमजोर तबके के विषय में बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता से काम किया है और बहुत सी ऐसी योजनाएं आप ले कर आई हैं, जिनके माध्यम से लोगों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा भी किया गया है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, अब समाप्त करें।

…(व्यवधान)

श्री अजय मिश्र टेनी : इससे उनकी वृद्धावस्था के लिए भी उनको सहायता मिलेगी तो मैं यह चाहता हूँ **कि** सरकार इसमें ऐसा संशोधन करे कि आंगनवाड़ी की सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे वह एक रुपये प्रति माह या दो रुपये प्रति माह का प्रीमियम सरकार उसको खुद जमा करे और आंगनवाड़ी की कार्यकत्ताओं को बीमा प्रदान करने का काम करें। काम के दौरान अगर कोई घटना उनके साथ हो जाती है तो उसका मुआवजा भी उनको मिलना चाहिए। काम के समय अगर मृत्यु होती है तो जो भी उसके लिए योजना बने उसको भी अच्छे से लागू करने कार्य आप करें।

आपका बहुत धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि अंबेडकर नगर से आने वाले हमारे भाई रितेश पांडे जी, जिन्होंने यह प्राइवेट रेजोल्युशन यहां पेश किया है, उसके ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं हेतु कल्याणकारी उपाय - निश्चित रूप से आज गांवों के अंदर, सुदूर डांढियों के अंदर अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर्स, नर्स के बाद स्वास्थ्य से ले कर, चाहे बच्चों के पालनपोषण से ले कर, मिड डे मील से ले कर, जितनी भी सरकारी कामकाज के अंदर की योजनाएं चल रही हैं, राज्य की योजनाएं चल रही हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आंगनवाड़ी कार्यकताओं एवं सहायिकाओं की है। ये हमारी बहनें हैं। सभापति महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि आजादी के 70 साल बाद जो सपना इस देश को आजाद कराने वाले लोगों ने सोचा था, आज ये बहनें भी हमेशा टकटकी लगा कर सरकार की तरफ देख रही

हैं। चूंकि आज सारे के सारे लोग दिल्ली की सरकार की ओर देख रहे हैं, क्योंकि राज्य के पास ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती हैं। हमारे राजस्थान के अंदर तो हालात यह हैं कि वहां एक ही रटी रटाई रट लगाई जाती है कि खजाना खाली है, पांच साल कुछ भी नहीं होगा। जो भी आंदोलित लोग होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। ...(व्यवधान) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए जो रेजोल्युशन पांडे जी ले कर आए हैं, महिलाएं, बच्चों एवं किशोरों की अनिवार्य स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं - ये सब उपलब्ध कराते हैं।

सभापति महोदय, निश्चित तौर पर यह जरूरी है कि इन्हें नियमित रोजगार मिले। स्थायी कर्मी की तर्ज पर वेतन मिले। इस रेजोल्युशन के माध्मय से चिंता कर के देश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया। चूंकि प्रधान मंत्री जी ने कुछ मानदेय इनका बढ़ाने का आदेश भी किया था। लेकिन वह बहुत कम था।

सभापति महोदय, कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि जब पूरा देश कोरोना से डर रहा था, लॉकडाउन भी लंबे समय तक चला। लोग एक दूसरे के पास जाने से डरते थे। परिवार के अंदर भी लोग ऐसे रहते थे, जैसे किसी को जानते भी नहीं है। उस सयम भी आंगनवाडी कार्यकत्ताओं और सहायकों ने बहुत सेवा की। हमारे वहां बहुत बड़ा आंदालन भी राजस्थान के अंदर चला, उस बात को भी मैं इसमें जोड़ूंगा। उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर होती है। वे लगातार राजधानी के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर बहुत बड़ी सेवा इनकी देखने को मिली।

ये हर समय सेवा के लिए तत्पर रहते थे। अपने बच्चों को छोड़ कर ये दूसरे की सेवा करने के लिए निकल पड़ते थे।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा वर्कर्स ने जिम्मेदारी से कोरोना काल में अपना काम किया। अभी राजस्थान के अन्दर इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। इनकी प्रमुख मांगें

थीं कि इन्हें संविदा से हटा कर नियमित किया जाए। कई लोग तो संविदा कर्मी भी नहीं हैं। महिला बाल विकास विभाग चाहे जब इन्हें निकाल देते हैं। मान लीजिए कि अगर इनकी सरपंच से या किसी नेता से पटरी नहीं बैठती तो बस एक जांच के बहाने उन्हें घर भेज दिया जाता है।

सभापति महोदय, इनके कल्याण को लेकर सदन में जो चिंता व्यक्त की गई है, मेरे से पूर्व हमारे सांसद ने आपको सारी बातें विस्तार से बताईं। अभी लोक सभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, जो यहां विराजी हैं, ने बताया कि दिनांक 01.10.2018 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय तीन हजार रुपये से बढ़ा कर 4500 रुपये, सहायिका का मानदेय 1500 से बढ़ा कर 2250 रुपये प्रति माह किया गया है। इस रिजॉल्यूशन में मानदेय को मासिक वेतन में बदलने की बात कही गयी है। मनरेगा के अन्दर भी न्यूनतम मजदूरी 200 रुपये से बढ़ा दी गई। आज जो मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी करता है, सात-आठ हजार रुपये तो वह भी कमा लेता है। मैं तो मांग करूंगा कि सरकारी नौकरी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो न्यूनतम वेतन 28,000 रुपये है, यह इन्हें भी मिले और इन्हें परमानेंट भी किया जाए। अल्प मानदेय व नाममात्र के प्रोत्साहन से इनकी आजीविका कैसे चलेगी? आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवनों में चलते हैं। वहां पर पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, इस पर सरकार को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि देश में 13,86,990 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 4,36,613 केन्द्रों पर शौचालय नहीं हैं जबकि 2,20,967 केन्द्रों पर पेयजल की सुविधा नहीं है। 3,58,486 केन्द्र किराए के भवनों में चल रहे हैं।

सभापति महोदय, इसके लिए हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। सांसद, विधायक और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वे भी अपने-अपने कोष से पैसे देकर आंगनबाड़ी के पक्के केन्द्र बना रहे हैं, लेकिन दो सालों के लिए तो आपने हमारा इलाज कर दिया। सांसद के पास बजट ही नहीं है तो वह कहां से करेगा? आप देखना, लोग नहीं बुलाएंगे। लोग कहते हैं कि एम.पी. साहब, आप क्या

करेंगे आकर, आपके पास बजट नहीं है, आप इसकी घोषणा नहीं कर सकते, इसलिए एम.एल.ए. को बुलाएंगे। इसके साथ-साथ आप इसका भी ध्यान लगातार रखें।

सभापति महोदय, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां 61,974 क्रियाशील आंगनबाड़ी केन्द्रों में 32,527 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही शौचालय है व 48,949 केन्द्रों पर पेयजल की व्यवस्था है। इस पर केन्द्र सरकार ध्यान दे।

सभापति महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा कर्मियों को स्थायी कार्मिक के तर्ज पर वेतन दी जाए। आशा सेविकाओं ने वेतन बढ़ोतरी व नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन किया। राजस्थान में इन्हें मात्र 2300-2400 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। इसलिए इसे बढ़ाया जाए क्योंकि इनसे शिक्षा, चिकित्सा तथा महिला बाल विकास विभाग के कार्य करवाए जाते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि जब ये महिलाएं आंदोलन करती हैं तो पिछले पन्द्रह सालों के अन्दर कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें जेल भी भेजा गया। राजस्थान सरकार मुकदमे वापस लेती है। मुझे राजस्थान का ही अनुभव है, लेकिन मैं केन्द्र सरकार से यह भी अपील करूंगा कि ऐसे मामलों में छोटी धाराओं के अन्तर्गत जितने भी मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं, उन्हें वापस लिए जाएं। इसके लिए केन्द्र निर्देशित करे और उन्हें परमानेंट करें, क्योंकि ये वे कड़ी है, जो देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सुख-सुविधा दिलाने का प्रयास करती है, काम करती है। गरीब से गरीब व्यक्तियों तक भी ये जाकर सरकारी सुविधाओं का लाभ देती हैं। आज आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो वहां बैठा जिले का जो ग्राम सेवक या पटवारी है, वह भी इनसे ही बात करके कराएगा, चाहे वह जनगणना का कार्य हो या दूसरे काम हों। सरकारी सेवाओं के लाभ ले रहे व्यक्तियों की गिनती करने का काम हो या कौन-सा पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा, हर व्यक्ति इन पर ही निर्भर करता है कि आप जाओ और हमें इसके बारे में लिख कर दीजिए। इनके ऊपर इतना बड़ा लोड है।

महोदय, मैं सरकार से माँग करता हूँ कि इस पर हमारी सरकार संवेदनशीलता से बड़ा कदम उठाए। आँगनबाड़ी की कार्यकर्ता और हमारी जो सहायिकाएँ हैं, इन बहनों का वेतन बढ़ाया जाए और इनको नियमित करें। आप लोगों ने महिला सशक्तिकरण का जो नारा दिया है, उसको और मजबूत करना चाहिए।

महोदय, हमारी बड़ी बहन स्मृति ईरानी जी इस विभाग की मंत्री है। आप निश्चित रूप से इन बहनों की तरफ देखेंगी। हमारा भारत तब ही मजबूत होगा, जब अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लगेगा कि वह दिल्ली के अंदर बैठा है। राजस्थान के जैसलमेर से लेकर कन्याकुमारी तक का व्यक्ति यह सोचे कि दिल्ली दूर नहीं है। यह तभी होगा, जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों को पढ़ाने के अच्छे स्कूल मिलेंगे, पौष्टिक खाना मिलेगा, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा मिलेगा और रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। ये लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं पाण्डेय जी को धन्यवाद दूँगा कि इन्होंने इनके लिए इतनी बड़ी चिंता की है। आज पूरा सदन इन आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएँ बहनों के बारे में चिंता करती है। हमारे जगदम्बिका पाल जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वह जमाना था जब मैं यूनिवसिर्टी-कॉलेज में पढ़ता था। उस समय मैंने एक दिन की मुख्यमंत्री वाली फिल्म भी देखी थी। उस एक दिन की मुख्यमंत्री वाली फिल्म हमारे पूर्व सीएम साहब को देखकर याद आती है। यह हमेशा इसके लिए बड़े आंदोलित रहते हैं। हम सब की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इन बहनों के लिए कुछ न कुछ अच्छा काम प्रधानमंत्री जी करें। यह मेरा निवेदन है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका मिला है। माननीय रितेश पाण्डेय जी के द्वारा यह एक संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी चर्चा में भाग लेने का अवसर आपने मुझे दिया है।

महोदय, मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से बातें कही है। उस संबंध में हमारी सरकार भी इन आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या सहायिकाओं के महत्व को रेखांकित करती है। उनके दायित्व या उनके कर्तव्य के बोध के साथ-साथ जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार सरकार ने एक मजबूत कदम उठा रही है। हमारे भारत के गाँव में रहने वाली महिलाएँ या बच्चे जो कुपोषित हैं, या जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उन बच्चों और महिलाओं के लिए किस तरीके से न्यूट्रिशन या टीकाकरण के संबंध में काम किया गया है, कुपोषण से एक स्वस्थ माँ और एक बच्चे को तैयार करने में इस आँगनबाड़ी के केन्द्र की भूमिका को निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में विस्तारित किया गया है।

आज पूरे भारत में एक तरह से ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल का यह एक केन्द्र बन गया है। उसी नाते आज भारत सरकार ने, पहले तो यह इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत आता था, लेकिन यह पहली बार हमारी सरकार या प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम केवल मालन्यूट्रिशन या चाइल्ड हंगर के बच्चों को स्वस्थ करने की दिशा में आँगनबाड़ी केन्द्रों से काम लें। इसके बजाय इन आँगनबाड़ी केन्द्रों को एक सक्षम आँगनबाड़ी केन्द्र और पोषण अभियान-2 में जोड़ा गया है। जैसाकि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अभी तक जो आँगनबाड़ी केन्द्र थे, वे कहीं पर दूरे थे, जहाँ पर उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। कई घटनाएँ हैं, उनका मैं उल्लेख नहीं करूँगा। कहीं पर दीवार गिर गई, सात बच्चों की डैथ हो गई। एक बार 2 बच्चे आँगनबाड़ी केन्द्र के पास तालाब में डूब गए।

आज सरकार ने यह तय कर लिया कि अब हम आँगनबाड़ी केन्द्रों को अपने स्कूल के ही कैम्पस से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे जो पोषण अभियान-2 है, उसमें छह महीने से 6 साल तक के बच्चों को तथा तीन से छह साल के बच्चों की देखभाल की जाएगी। आँगनबाड़ी केन्द्र की उन महिलाओं को ट्रेंड भी किया जाएगा। हमारे बच्चों के खेलने की जो उम्र होती है, उसके लिए भी सही तरीके से काम किया जा सकता है।

यह एक बड़ी योजना बनाई है। इससे साफ हो गया कि आंगनवाड़ी महिलाओं की भूमिका दिन-ब-दिन बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। यह काम वर्ष 1975 में शुरू हुआ। वर्ष 1975 में उस समय बेसिक था कि गांव में माल न्यूट्रिशन या चाइल्ड हंगर के लिए यह विभाग बनाया गया। वर्ष 1978 में जब मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे, तो इसको देश के 6 लाख गांवों में डिसकंटीन्यू कर दिया गया। मैं धन्यवाद दूंगा कि वर्ष 2002 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने टेंथ फाइव ईयर प्लान में इसे फिर से रीलांच किया कि देश की महिलाओं और बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से जीवित करने का काम किया, जो आज इतना विस्तारित हुआ है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह कार्यक्रम था, इसमें जो आईसीडीएस है, उसको आंगनवाड़ी के साथ लिंक किया और इसमें भी फोकस किया। This is when ICDS was linked to the anganwadis with a focus on girl child by providing girls the same resources as boys. आप इस देश की मानसिकता जानते हैं कि आज से 40-50 साल पहले बच्चे पैदा होते थे, तो गांवों में कितना महत्व रहता था, घरों में खुशियां मनाई जाती थीं और थालियां बजाई जाती थीं। अगर कहीं बेटी पैदा हो गई, तो घर की महिलाओं के जैसे चेहरे उतर जाते थे। उस समय भ्रूण हत्या और जिस तरह का भेद था, उस भेद को दूर करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में आया कि इन आंगनवाड़ी केंद्रों को उन गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेट करने का काम, उनको स्वस्थ रखने का काम, लड़कों की बराबरी का स्थान देने का काम, उन लड़कियों पर फोकस किया जाए, इसलिए इन आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने का काम किया। इसका वर्ष 2013-14 में 16,312 करोड़ रुपये का बजट था। मैं धन्यवाद दूंगा कि वर्ष 2020-21 में 20,033 करोड़ रुपये का बजट हुआ है। लगभग 4 हजार करोड़ रुपये बढ़ाये हैं। निश्चित तौर से कितना बड़ा फोकस है कि हमारा हर बच्चा और बच्ची जो पैदा हो, वह कुपोषित न हो, मां भी स्वस्थ हो, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हों।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान के लिए मैंने कहा, सक्षम आंगनवाड़ी वही है, जैसा हमारे टेनी मिश्रा जी और दूसरे सदस्यों ने कहा कि

आंगनवाड़ी केंद्रों में जो दूर थे, वहां न पीने के पानी की सुविधा थी, न टॉयलेट की सुविधा थी, न कहीं कुछ सुविधा थी। इसके लिए एक फैसला लिया गया कि Anganwadi Centres will be strengthened with high quality infrastructure, play equipment and would be made well ventilated, well designed and child friendly. मतलब हम उस स्कूल को एक घर जैसा माहौल दें कि बच्चा अपने को जिस तरह मां के साथ फ्रैंडली महसूस कर रहा हो, उसी तरह से आंगनवाड़ी केंद्र में आने के बाद भी वैसा महसूस करे। वह चाइल्ड फ्रेंडली हो, ऐसा आंगनवाड़ी केंद्र बने। काफी अच्छा डिजाइन्ड हो, वेंटिलेटेड हो और सारी सुविधाओं के साथ हो। मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि पहली ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की ट्रेनिंग आंगनवाड़ी महिलाओं को देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया है, तो निश्चित तौर से इससे एक क्वॉलिटेटिव चेंज आएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स हाई स्कूल पास होंगी, जो एक टीचर के रूप में टेन प्लस टू होंगी, तो उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया जाएगा। 6 महीने के प्रोग्राम के बाद वे केवल पुष्टाहार नहीं देंगी या न्यूट्रिशन के लिए जो पुष्टाहार है या रेडी टू ईट है, केवल वही खिलाने का काम नहीं करेंगी, बल्कि एक टीचर के रूप में काम करेंगी। तीन साल की उम्र तक तो कोई पढ़ाई नहीं होती है। उन बच्चों के साथ, जब उनका दिमाग तेजी से विकास की ओर रहता है, तो कम से कम वह किसके साथ है, यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। जो हाई स्कूल से कम पढ़ी-लिखी होंगी, उनके लिए भी यह तय हुआ कि उनको एक साल का डिप्लोमा करायेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, जिससे कि वे कम से कम उन बच्चों के विकास में भागीदार बन सकें। These programmes may be run through digital/distance mode using DTH channel as well as smart phones also. स्मार्टफोन देने की भी कल्पना थी, अब यह भी साकार हो रहा है या जो डीटीएच चैनल के माध्यम से भी हो रहा है। आज हम कितना फोकस्ड हो गए हैं, हम आंगनबाड़ी महिलाओं को टीचर के रूप में बच्चों के साथ फ्रेंडली कर सकें, इस तरीके से किया गया। आज तय हो गया है कि जो आंगनबाड़ी केन्द्र अभी तक स्टैंड अलोन है, अब

आंगनबाड़ी को लोकेट करके प्राइमरी स्कूल में बदलेंगे, Specially trained in the curriculum and pedagogy of ECCE यह इस तरीके से होगा। आज आंगनबाड़ी का लाभ भी मिल रहा है, आज हमने आंगनबाड़ी का विस्तार किया है, वह निश्चित रूप से देश के सभी गांवों और मजरे तक में किया है। आज आंगनबाड़ी की देन है कि वर्ष 2020 तक आठ करोड़ पचपन लाख इसके लाभार्थी हो गए हैं। छह महीने से छह साल तक के बच्चों की संख्या छह करोड़ छप्पन लाख तक हो गई है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी मांग लेकर मैं मंत्री जी से भी मिला हूं। अभी खुद बेनीवाल जी ने 2018 का उल्लेख किया कि किस तरह से मानदेय बढ़ाया गया है। वर्ष 2012 में आंगनबाड़ी के लोगों को मात्र तीन हजार रुपये मिलते थे। एकमुश्त मानदेय तीन हजार रुपये से बढ़ाकर पैंतालीस सौ रुपये करने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। सुदूर अंचल में जो महिलाएं मानदेय पर काम कर रही थीं, आनरेरियम पर काम कर रही थी, सहायिका का मानदेय दो हजार पचास से बढ़ाकर पैंतीस सौ रुपये कर दिया गया, हैल्पर को पन्द्रह सौ रुपये से बढ़ाकर दो हजार दो सौ पचास रुपये कर दिये गये क्योंकि हम लोगों की ऐसी भावना थी। हम लोग लगातार माननीय मंत्री जी से इसके लिए मिलते रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से भी कहते रहे हैं। किसी सरकार का ध्यान आंगनबाड़ी की तरफ नहीं गया था। आंगनबाड़ी महिलाएं जाड़ा, गर्मी और बरसात में डोर स्टेप पर पुष्टहार की डिलेवरी करती हैं, रेडी टू ईट की डिलेवरी भी करती है, इस लॉकडाउन में भी काम किया, इसका सभी ने उल्लेख किया है।

प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, नर्सों और आशा बहनों को कोरोना वॉरियर्स कहा, उसी तरह से हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कोरोना वॉरियर्स माना था और उन्हें पचास लाख रुपये का इन्श्योरेंस कवरेज दिया था। अगर कोविड-19 के दौरान दुर्भाग्य से किसी की मौत हो गई तो निश्चित रूप से उसके परिवार के आश्रित को पचास लाख रुपये मिलेगा। जहां

एक तरफ इनका दायित्व बढ़ रहा है, अब आंगनबाड़ी का काम केवल पुष्टाहार तक सीमित नहीं है, पल्स पोलियो का अभियान होता है तो भी आंगनबाड़ी केन्द्र काम करता है, जब जनगणना का कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में इनको लगाया जाता है।

मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ये बातें इसलिए ला रहा हूं क्योंकि वे इसे जानती हैं। किसी राज्य का मानदेय कितना है, किसी राज्य का मानदेय कुछ है, इसमें किस तरह से एकरूपता लाई जा सके, आज इनकी इतनी बड़ी भूमिका है, चाहे प्रेगनेंट महिलाएं हों या लैक्टेटिंग मदर्स हों, वे करीब एक करोड़ अडसठ लाख हैं, इनके बीच वे काम कर रही हैं। इनको किस तरीके से राज्यों के माध्यम से और मजबूत किया जा सके क्योंकि आज इनकी भूमिका कम नहीं हो सकती।

इनकी भूमिका पोषण अभियान-॥ से भी जुड गयी है। आंगनबाड़ी केन्द्रों को जिस तरह से केन्द्र सरकार मदद कर रही है, देश की एक जेनरेशन को बदलने की बात कर रहे हैं। हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ तुलना नहीं करेंगे। हम बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका के साथ तुलना नहीं कर सकते। आज हमारे बच्चों के न्यूट्रिशन पर सरकार ध्यान दे रही है।

अगर हमें विश्व गुरू बनना है तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी आने वाली जनरेशन है, आने वाली जनरेशन निश्चित रूप से दुनिया में विश्व गुरू बनकर दिखाएगी। आज हम केवल शहरों तक सीमित नहीं हैं। आज हम देश के लाखों गांवों तक जा रहे हैं, आज देश में तेरह लाख तिरासी हजार आपरेशनल आंगनबाड़ी सेंटर है, जहां पहले पानी उपलब्ध नही था, आज ग्यारह लाख सड़सठ हजार केन्द्रों में ड्रिंकिंग फैसिलिटी है, दस लाख उन्नीस हजार आंगनबाड़ी केन्द्र आपरेशनल हैं, वह गवर्नमेंट के स्कूल बिल्डिंग में भी आ गए हैं।

टाएलेट फैसिलिटी हर एक गांव में हर घर में देने की बात चल रही थी। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी टाएलेट फैसिलिटी हो, ऐसा हमने किया। आंगनवाड़ी

वर्कर्स देश में भारी संख्या में हैं, 13 लाख 29 हजार हैं और 11 लाख 85 हजार हैल्पर्स हैं। इनका रोल क्या है? इसके बारे में पूरा देश नहीं जानता। जब यूनिसेफ ने कहा, संयुक्त राष्ट्र ने कहा, शास्त्री जी ने कहा कि देश में बच्चों की मृत्यु दर कम होना चाहिए। दुनिया ने इसे गंभीरता से लिया हो या न लिया हो, लेकिन हमारे देश ने लिया। चाहे बच्चों की बढ़ती हुई मृत्यु दर की बात हो या जच्चा की प्रेगनेंसी के समय मृत्यु दर की बात हो, इसे कैसे कम किया जाए, इसे हमारे यहां बहुत गंभीरता से लिया गया। इनके माध्यम से गांवों में काम शुरू हुआ, मॉर्टेलिटी रेट 46 परसेंट था, जो कि घटकर वर्ष 2017 में 33 प्रतिशत रह गया। बच्चों के कुपोषण में इतना रिडक्शन आया है।

यह बहुत गंभीर विषय है और इस दिशा में बहुत प्रयास हुआ है। जहां पहले पुष्ट आहार रैडी टू ईट था और अब पोषण अभियान में इन बच्चों पर खास फोकस किया जा रहा है, चाहे गर्ल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड हो, कुपोषित न हों। वर्ष 2005-06 तक 48 परसेंट यानी देश की लगभग आधी आबादी कुपोषित थी। यह भारत साउथ ईस्ट एशिया का थर्ड वर्ल्ड कहलाता था।

मैं वैक्सीन के विषय पर नहीं आना चाहता हूं, लेकिन दुनिया में कोविड की चुनौतियों का माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सामना किया है। अब तो हमारे यहां वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन आसपास के किसी देश ने नहीं निकाली। हम 22 देशों को वैक्सीन दे रहे हैं। नेबर फर्स्ट को मुफ्त दे रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। जिस तरह से संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर आए, आज वैक्सीन केवल भारत के लोगों के जीवन की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया के लिए संजीवनी बनकर पूरे विश्व के लोगों की रक्षा कर रहा है।

यह सरकार का प्रयास एक द्योतक है, एक प्रतीक है। कोविड की चुनौती पर चीन हैल्पलैस हो गया। कल रात मैं टीवी देख रहा था, जर्मनी में मार्च तक लॉक डाउन हो गया, इंग्लैण्ड में लॉक डाउन है। हम भारत में फिर से सामान्य स्थिति में बैठे हैं। हमने कंट्रोल किया है, 97.54 परसेंट रिकवरी रेट हो गया, 1.4 परसेंट दुनिया का सबसे मिनिमम, सबसे नॉमिनल डैथ रेट है।

मैं वर्ष 2015-16 की बात कर रहा हूं, नेशनल फैमिली हैल्थ–iv की रिपोर्ट है और नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे–v की रिपोर्ट नहीं आई है। 18 राज्यों में इसे लागू कर दिया। वर्ष 2015-16 में हमारी सरकार आई और हमने इस पर फोकस किया जिससे कुपोषित बच्चों की संख्या 48 परसेंट से घटकर 38 परसेंट हो गई। माननीय मंत्री जी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे–v की रिपोर्ट के बारे में बताएंगी तो मेरे ख्याल से और भी घट गया होगा।

आईसीडीएस इम्युनाइजेशन का काम कर रहा है, न्युट्रिशन का काम कर रहा है, हैल्थ चैकअप का काम कर रहा है, रैफरल सर्विसेज का काम कर रहा है, प्री-स्कूल एजुकेशन का काम कर रहा है। न्युट्रिशन एंड हैल्थ इन्फार्मेशन, 15 से 45 साल तक की महिलाएं के बीच में काम कर रहा है। इस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि कोविड-19 में आशा बहनें, बहुएं गांवों में जा रही थीं, उनको 2000 रुपये अलग से दिए गए थे। इंश्योरेंस कवरेज आंगनवाड़ी के लोगों को दिया गया था लेकिन इनको यह पैसा नहीं मिला। इस बात पर विचार किया जाए। कोविड-19 में आशा बहनें या बहुएं घर-घर में जा रही थीं, उसी तरह से आंगनवाड़ी महिलाओं ने भी काम किया। उनके लिए भी यही सुविधा होनी चाहिए थी।

लॉक डाउन में जो आंगनवाड़ी सैंटर्स ने काम किया है। 'As regards the functioning of Anganwadi Centres during COVID-19, distribution of food items and nutrition was supported by Anganwadi Workers once in 15 days at the doorstep of beneficiaries.'

21.00hrs

इसका मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों पर ही नहीं बल्कि आंगनवाड़ी केंद्रों से बाहर निकलकर हमारी आंगनवाड़ी की बहनें, हमारी सहायिका लॉकडाउन के दौरान भी उसी तरह से कोरोनो योद्धा की तरह लोगों के घरों पर जाकर, जहां गर्भवती महिलाएं थीं या जहां छोटे बच्चे थे, उनके बीच में जाकर, जिस प्रकार से रेडी टू ईट, पुष्ट आहार या अनाज बांटने का काम किया, मैं निश्चित तौर से इस सदन के

माध्यम से अपनी उन आंगनवाड़ी बहनों को भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन महिलाओं को देश सलाम कर रहा है। कोरोना में जहां बड़े-बड़े लोग डर गए थे, लोग अपनी दहलीज से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग अपनी जिन्दगी की हिफाजत की दुआ कर रहे थे, वहां हमारी ये बहनें प्रधान मंत्री मंत्री मोदी जी के आह्वान पर अपनी जान को जोखिम में डालकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक दूसरों की जिन्दगी बचाने का काम किया।

आज पोषण अभियान में हमारे मंत्री जी के विभाग ने 10 लाख 22 हजार आईसीडीएस वर्कर्स को दिसम्बर, 2020 तक ट्रेंड कर दिया। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है। गांव में इनके केंद्र पर कोई नहीं जाता था। आंगनवाड़ी के नाम पर एक जमाना था कि किस तरीके से वे महिलाएं उसी केंद्र पर रहती थीं। लोगों को लगता था कि पुष्ट आहार नहीं पहुंच रहा है। पुष्ट आहार था भी, तो स्टेट लेवल पर जिस गुणवत्ता का होना चाहिए था, वह नहीं था। आज यहां से यह कोशिश होती। हम फेडरल स्ट्रक्चर में हम रह रहे हैं।

माननीय सभापति: एक सेकेंड जरा रूकिए। नौ बज रहे हैं। सदन की सहमति हो तो अभी दो घंटा समय बढ़ा दिया जाए। बाद में, फिर देखेंगे जैसी आवश्कयता होगी।

श्री जगदम्बिका पाल: बारह बजे तक कर दीजिए।

माननीय सभापति: इनको पूरा कर लेने देते हैं, फिर उसको आगे कर लेंगे। पाल साहब विषय को पूरा कर दीजिए। उसके बाद जीरो ऑवर ले लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल: हमारा कंटिन्यू कर दीजिए।

माननीय सभापति: ठीक है।

श्री जगदम्बिका पाल: धन्यवाद।

माननीय सभापति: आप अगली बार करना चाहते हैं? अभी पूरा नहीं करेंगे?

श्री जगदम्बिका पाल: नहीं सर, अभी तो शुरुआत है। परम्परा यही है कि कंटिन्यू हो जाती है। ...(व्यवधान) आप 'जीरो ऑवर' कर दीजिए। अभी बहुत-सी बातें कहनी हैं।

माननीय सभापति: ठीक है।